1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	6	682.87	77.52	85.36	
14.	मणीपुर	3	61.23	8.25	7.65	
15.	मेघालय	–	0.00	1.53	0.00**	
16.	मिजोरम	1	44.24	4.26	4.26	
17.	नागालैण्ड	–	0.00	2.05	0.00**	
18.	उड़ीसा	5	401.84	48.93	50.23	
19.	पंजाब	2	226.12	26.73	26.73	
20.	राजस्थान	10	655.73	75.08	81.97	
21.	सिक्किम	–	0.00	0.62	0.00**	
22.	तमिलनाडु	15	657.90	74.70	82.24	
23.	त्रिपुरा	1	41.30	5.48	5.16	
24.	उत्तर प्रदेश	42	2623.04	296.27	327.88	
25.	पश्चिम बंगाल	3	324.38	39.19	39.13	
26.	ए० एण्ड एन० द्वीप समूह	–	0.00	0.00	0.00††	
27.	चण्डीगढ़	–	0.00	0.00	0.00††	
28.	दादरा व नगर हवेली	–	0.00	0.38	0.00 स्कीमें नहीं मिली	
29.	दमन व द्वीव	–	0.00	0.00	0.00††	
30.	दिल्ली	–	0.00	1.77	0.00††	
31.	लक्ष्यद्वीप	–	0.00	0.98	0.00††	
32.	पांडिचेरी	–	0.00	1.11	0.00 स्कीमें नहीं मिली	
	योग	147	9419.66	1200.00	1171.44	

**कस्बे अनुमोदित मानदण्ड/दिशानिर्देश के अनुसार नहीं हैं ।
††20,000 से कम की आबादी वाले शहर नहीं हैं ।

शहरी विकास के लिए वित्तीय सहायता

5162. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शहरी विकास के लिए देश के कुछ शहरों को कुछ वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस श्रेणी के अंतर्गत कौन-कौन से शहर हैं;

(ग) क्या गुजरात को, विशेष रूप से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जाम नगर शहरों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन शहरों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) "शहरी विकास" राज्य का विषय है और योजना आयोग यह अपेक्षा करता है कि शहरी विकास की सभी परियोजना राज्य योजना का भाग होनी चाहिए । तथापि, कतिपय महानगरों की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सहायता हेतु राज्य सरकारों की निरन्तर मांगों तथा राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मेगा शहरों के विकास हेतु वर्ष 1993-94 के दौरान एक केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रारम्भ की गई है । यह स्कीम, 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर पर लागू है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Depletion of ridge in Delhi

5163. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ridge in Delhi, which acts as the lungs of the polluted city and as the barrier between the Thar desert and the plains, has become a victim to garbage dumps, slums, paramilitary camps, place of worship, schools and mines ; and

(b) if so, whether Government propose to take any adequate and firm steps to remove all forms of encroachment from the Ridge and ensure its protection and that of the city of Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) The DDA has initiated concerted steps to reclaim encroached land under its control in Delhi.

Integrated development of Small and Medium towns

5164. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Central Government have revised guidelines for the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Development of Small and Medium towns :

(b) if so, the details thereof ;

(c) the names and the number of towns in Orissa given grants for development under the above Central scheme so far ;

(d) whether Government proposed to develop Keonjhargarh in Orissa under that scheme :

(e) if so, the funds sanctioned for the purposes ; and

(f) the towns which are identified for development under that scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) Information is given in enclosed statement-I (*See* below).

(c) During the period 1979-80 to 1993-94, 27 towns in Orissa State have been covered under the IDSMT Scheme. The names of towns are given in the enclosed statement-II (*See* below).

(d) Project proposals seeking Central assistance under IDSMT Scheme are formulated by the State Governments and submitted to the Government of India for approval. The Government of Orissa have not identified Keonjhargarh town in its priority list of 8 towns submitted to the Government of India for inclusion under IDSMT Scheme during the 8th Plan period.

(e) Does not arise

(f) The 8th Plan priority list of Towns received from government of Orissa is enclosed as statement-III